वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट अनुमानों पर माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2013–2014 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

हमने वर्ष 2012–2013 के बजट भाषण में वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश, जो विगत 5 वर्षों में अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत पीछे छूट गया है, को पुनः विकास के पथ पर समाजवादी सोच के साथ तीव्र गति से आगे ले जाना है ।

वर्ष 2012–2013 का बजट पारित होने के बाद से हमें बमुश्किल 7–8 माह मिले हैं किन्तु मुझे आज आपको यह बताते हुये अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि इतनी अल्प अवधि में हमने प्रदेश की जनता से किये गये वायदे पूरे किये हैं जिससे हमारी सरकार पर लोगों का विश्वास दृढ़ हुआ है । वर्ष 2013–2014 में हमारा लक्ष्य इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के सुदूरगामी अंचलों तक प्रभावशाली ढंग से पहुँचाने का है । इस संकल्प के साथ मैं आज वर्ष 2013–2014 का बजट माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मान्यवर, पिछले वर्ष 01 जून को हमारी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करते हुये मैंने कहा था कि प्रदेश को विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जाना है । हमारी प्राथमिकताओं में नौजवान

साथी, अल्पसंख्यक, किसान, विद्यार्थी, रिक्शा चालक, बालिकायें विशेष रूप से शामिल हैं । समाजवादी विचारधारा के प्रणेता डॉ0 राममनोहर लोहिया जी ने लाखों बदनसीब और उपेक्षित साइकिल रिक्शाचालकों की समस्या को लोक सभा में सबसे पहले उठाया था । रिक्शाचालकों की समस्या के माध्यम से लोहिया जी ने वास्तव में उन लाखों बेरोजगारों की समस्या को उभारा था जो अपना पेट पालने के लिये शहरों में चले आते हैं । इनकी व्यथा को वाणी देते हुये उन्होंने कहा था कि ये लोग शहरों में चले आते हैं और शहरों में न इनका कोई रिश्तेदार होता है और न रहने का कोई ठिकाना । देर रात तक रिक्शा चलाना पड़ता है । रिक्शाचालकों की इस पीड़ा को समझते हुये हमारी सरकार द्वारा शहर के रिक्शाचालकों को मोटरचालित रिक्शे निःशुल्क दिये जाने का निर्णय लिया गया था और इसके क्रम में दिनाँक 09 फरवरी, 2013 को रिक्शाचालकों को मोटर चालित रिक्शों का ट्रायल तौर पर वितरण प्रारम्भ किया गया है ।

वर्ष 2013–2014 के बजट का विशिष्ट पहलू यह है कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गयी है । जहाँ राजस्व व्यय में वर्ष 2012–2013 के सापेक्ष केवल 9.8 प्रतिशत की वृद्धि इस बजट में की गयी है वहीं पूँजीगत पक्ष में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी । इसी अनुक्रम में इस बजट में प्लान पक्ष को वरीयता देते हुए, वर्ष 2012–2013 के सापेक्ष 19.4 प्रतिशत की

वृद्धि की गयी है जबकि नॉन–प्लान पक्ष में यह वृद्धि केवल 7.1 प्रतिशत ही है ।

मान्यवर,

उत्तर प्रदेश विकास के एक नये मार्ग पर अग्रसर है । विकास को ठोस और समयबद्ध कार्यक्रमों की जमीन पर उतारा जा रहा है । एक ऐसी जमीन पर जो प्रदेश के हर क्षेत्र, हर वर्ग–समुदाय और आखिरी आदमी की खुशहाली से जुड़ी है ।

मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि प्रदेश के विकास के व्यापक एजेण्डे को विभागवार और योजनावार कार्य बिन्दुओं में विभाजित कर प्रगति का सतत् अनुश्रवण किये जाने की प्रभावी व्यवस्था की गयी है जिसके सकारात्मक परिणाम हुये हैं ।

मान्यवर, वर्ष 2013–2014 के बजट के बारे में चर्चा करने से पहले, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष हमारी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सरकार द्वारा लिये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा रखना चाहूँगा ।

- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ती आबादी के दृष्टिगत एक विश्वसनीय पब्लिक ट्रान्सपोर्ट की नितान्त आवश्यकता है । देश की राजधानी तथा कई राज्यों की राजधानियों में मैट्रो रेल बन गई है या बन रही है । अब समय आ गया है कि लखनऊ के लोगों को भी यह सुविधा बिना किसी विलम्ब के उपलब्ध करायी जाय । मुझे माननीय

सदन को सूचित करते हुए अपार खुशी है कि हमारी सरकार के द्वारा लखनऊ में पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हेतु मैट्रो रेल योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है । इस सुविधा से जहाँ एक ओर लखनऊ नगरवासियों को दिन–प्रतिदिन की यातायात की समस्या से छुटकारा मिलेगा वहीं दूसरी ओर लखनऊ की देश के ही नहीं अपितु विश्व के विकसित शहरों में गिनती होगी ।

- गत पेराई सत्र 2011–2012 में गन्ना किसानों को लगभग 18,200 करोड़ रुपये की धनराशि का गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान किया गया । सरकार द्वारा बढ़ाये गये गन्ना मूल्य के फलस्वरूप वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना कृषकों को लगभग 21,000 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा जो गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 3,000 करोड़ रुपये अधिक होगा ।

- सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है ।

- न्यून सकल नामांकन दर वाले 41 जनपदों में से शेष 36 जनपदों में नये मॉडल राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही की जा रही

है । इन 36 जनपदों में से 05 जनपद अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद हैं ।

- डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लगभग 10,000 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है । वर्ष 2013–2014 में उक्त में से 2,100 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 36,000 रुपये से कम हो और जिनके नाम बी0पी0एल0 सूची में न होने के कारण इन्दिरा आवास की सुविधा से वंचित हैं, उन्हें 2 कमरों का अच्छा आवास देने के लिये राज्य सरकार द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है । इस योजना में प्रति आवास के निर्माण हेतु एक लाख रुपये का अनुदान तथा सोलर लाईट हेतु पन्द्रह हजार रुपये की सीमा तक अनुदान दिया जायेगा । इस योजना हेतु 520 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- आगरा से लखनऊ तक एक नये 8 लेन एक्सेस कन्ट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे का निर्माण निजी सहभागिता से कराया जायेगा । इस परियोजना की कन्सेप्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है जिसके आधार

पर ब्रॉड एलाइनमेन्ट निर्धारित हो चुका है । "प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कन्सल्टेन्ट" का चयन किया जा चुका है जिसके द्वारा परियोजना की "फीजिबिलिटी स्टडी" तैयार की जा रही है ।

- दिल्ली – सहारनपुर – यमुनोत्री राज्य राजमार्ग, बरेली–अल्मोड़ा राज्य राजमार्ग, वाराणसी–शक्तिनगर राज्य राजमार्ग तथा मेरठ–करनाल राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है । यह सभी मार्ग 04 लेन मार्ग होंगे ।

- शाहजहाँपुर – हरदोई – लखनऊ मार्ग, गोरखपुर – महराजगंज मार्ग, बलरामपुर – गोण्डा – जरवल मार्ग, अलीगढ़ – मथुरा मार्ग, एटा – शिकोहाबाद मार्ग तथा मुजफ्फरनगर – सहारनपुर वाया देवबन्द मार्ग को सार्वजनिक – निजी सहभागिता से 04 लेन किये जाने का कार्य वर्ष 2013–2014 में प्रारम्भ किया जायेगा ।

- 259 पुलों का निर्माण कार्य जिनकी लागत लगभग 4,500 करोड़ रुपये है, प्रगति पर है । इन सेतुओं मे से गंगा नदी पर 12 सेतु (वाराणसी में 02, मिर्जापुर में 02, गाजीपुर में 02, फर्रूखाबाद में 01, प्रतापगढ़ में 01, बुलन्दशहर में 01, कासगंज में 01, उन्नाव में 01 तथा मेरठ में 01) बनाये

जायेंगे । यमुना नदी पर 13 सेतु (आगरा में 01, बाँदा में 03, फिरोजाबाद में 01, चित्रकूट में 01, जालौन में 02, मथुरा में 02, हमीरपुर में 01 और इटावा में 02) बनाये जायेंगे ।

- जनपद रामपुर में दो फ्लाईओवर का निर्माण कराया जायेगा जिनमें से एक की लागत लगभग 19 करोड़ रुपये तथा दूसरे की लागत लगभग 160 करोड़ रुपये है ।

- कानपुर नगर में गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन के निकट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य, जिसकी लागत लगभग 45 करोड़ रुपये है, कराया जायेगा ।

- जनपद फैजाबाद के विधानसभा क्षेत्र रूदौली में गोमती नदी पर एक सेतु का निर्माण कार्य कराया जायेगा, जिसकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है । गोरखपुर में गोरखपुर–नौतनवा रेल सेक्शन के अन्तर्गत रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य कराया जायेगा, जिसकी लागत लगभग 51 करोड़ रुपये है ।

- लखनऊ में लोरेटो कॉन्वेन्ट चौराहे से तेलीबाग मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य कराया जायेगा जिसकी लागत लगभग 40 करोड़ रुपये है । लखनऊ में ही आलमनगर रेलवे स्टेशन

के पास रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य कराया जायेगा, जिसकी लागत लगभग 37 करोड़ रुपये है ।

- प्रदेश के जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़े जाने की योजना के अन्तर्गत कसया से देवरिया, कासगंज से एटा, कालपी से हमीरपुर, तथा मुरादाबाद से सम्भल मार्गों को 04 लेन का किया जायेगा ।

- गाजियाबाद शहर में यातायात के दबाव को देखते हुये हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि गाजियाबाद शहर में "नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड परियोजना" क्रियान्वित की जायगी, जिसकी लम्बाई लगभग 20 किलोमीटर होगी ।

- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जायेगी । इस कार्य के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधीन जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जायेगी । इस कार्य के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा दो नये विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है । इनमें से एक विश्वविद्यालय इलाहाबाद में तथा दूसरा विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर में स्थापित किया जायेगा ।

- अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगियों के तीमारदारों के लिए ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके फलस्वरूप उन्हें अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था । हमारी सरकार ने इस समस्या के निराकरण हेतु यह निर्णय लिया है कि सामुदायिक केन्द्रों पर रोगी आश्रय स्थल भवनों का निर्माण कराया जाय । इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिए 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु नई तकनीक "थ्री–डी जिओ – स्पेशियल डेटाबेस हाई रिजॉल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी सिस्टम" को विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है । इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक प्रकार के नक्शों को इन्टीग्रेट किया जायेगा तथा सेटेलाइट डेटा को शामिल किया जायेगा । इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश में विकास कार्यों की मॉनीटरिंग तथा प्लानिंग करने में सुविधा

होगी और धनराशि का सही तथा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँच सकेगा ।

- महिलाओं के साथ की जाने वाली बदसलूकी को रोकने के लिये वीमेन पावर लाइन 1090 सेवा प्रारम्भ की गयी है जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं । इस सेवा की सफलता से प्रेरित होकर अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं । हमारी सरकार महिलाओं के आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिये कृतसंकल्प है ।

- सामान्य–जन को आवश्यकता के समय तत्काल मदद पहुँचाने के लिये हमारी सरकार के द्वारा पुलिस के लिये जी0आई0एस0 / जी0पी0एस0 उपकरण तथा वेहिकल ट्रैकिंग रिस्पॉन्स सिस्टम से युक्त अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जा रहे हैं । प्रथम चरण में यह कन्ट्रोल रूम लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर एवं गाजियाबाद में स्थापित किये जायेंगे । इन नगरों में ट्रैफिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी स्थापित किये जा रहे हैं ।

- हमारी सरकार के द्वारा आशीर्वाद–बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना शुरू की गयी

है । वर्ष 2012–2013 में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की सुविधा दी जा रही है । वर्ष 2013–2014 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ–साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों, अनाथालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले लगभग 2 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य है ।

- हमारी सरकार के द्वारा इमरजेन्सी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के अन्तर्गत समाजवादी स्वास्थ्य सेवा की एम्बुलेंसों को संचालित करने की योजना प्रारम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत इस समय 988 एम्बुलेन्स संचालित की जा रही हैं, जो अपने आप में पूरे देश में एक कीर्तिमान है । दिनाँक 15 फरवरी, 2013 तक इस योजना के अन्तर्गत 1.91 लाख से ज्यादा प्रदेश वासियों को लाभ प्राप्त हो चुका है, जिनमें 01 लाख से भी ज्यादा महिला लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें प्रसूति सम्बन्धी चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी गयी है ।

- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा इन्हें प्रबन्धन की नई तकनीकों में दक्ष करने के लिए लखनऊ

में डॉ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी की स्थापना की जायेगी ।

- बेसिक शिक्षण संस्थाओं के पेंशनरों की पेंशन का भुगतान कोषागारों के माध्यम से पहली बार 01 जनवरी, 2013 से प्रारम्भ कराया गया । यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिससे बेसिक शिक्षा के सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को बिना किसी असुविधा/विलम्ब के पेंशन का भुगतान उनके खाते में किया जा रहा है ।

- सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं पेंशनरों की पेंशन का भुगतान ई–पेमेण्ट द्वारा सीधे उनके खाते में किये जाने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है ।

आगरा समिट

मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि 27 जनवरी से 29 जनवरी, 2013 तक आगरा में "ग्लोबल पार्टनरशिप समिट, 2013" आयोजित की गयी जिसमें 1,300 से अधिक निवेशकों, उद्यमियों, विदेशी राजदूतों एवं कॉर्पोरेट जगत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया ।

इस सम्मेलन में हमारी सरकार द्वारा बनायी गयी नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, सूचना प्रौद्योगिकी

नीति, सौर ऊर्जा नीति, चीनी उद्योग को–जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति तथा पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुये कॉमर्शियल लेयर्स एवं ब्रॉयलर्स पैरेन्ट फार्म खोले जाने संबंधी नीति का प्रस्तुतिकरण किया गया ।

इन सभी नीतियों का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अनुकूल वातावरण सृजित करना है । मेरा पूर्ण विश्वास है कि इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में अधिक से अधिक पूँजी निवेश आकर्षित होगा जिससे जहाँ एक ओर हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा वहीं दूसरी ओर प्रदेश का आर्थिक विकास भी होगा ।

मान्यवर,

अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूँगा ।

- वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिये प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख इक्कीस हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रुपये (2,21,201.19 करोड़ रुपये) है जो वर्ष 2012–2013 के बजट के सापेक्ष 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।
- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2012–2013 की अपेक्षा लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है ।

- वर्ष 2013–2014 के बजट में सात हजार सात सौ सत्तासी करोड़ अस्सी लाख रुपये (7,787.80 करोड़ रुपये) की 219 नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं ।

- अवस्थापना सुविधाओं, यथा–सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिये छब्बीस हजार छः सौ इकतालिस करोड़ रुपये (26,641 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2012–2013 से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है ।

- त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिये सत्रह हजार एक सौ चौहत्तर करोड़ रुपये (17,174 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

- शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिये बत्तीस हजार आठ सौ छियासी करोड़ रुपये (32,886 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु दस हजार छः सौ पैंतालिस करोड़ रुपये (10,645 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2012–2013 की तुलना में लगभग 12.1 प्रतिशत अधिक है ।

- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के लिये बीस हजार दो सौ बानवे करोड़ बानवे लाख रुपये (20,292.92 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है, जो वर्ष 2012–2013 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है ।

वर्ष 2013–2014 के बजट में सम्मिलित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

मान्यवर, विभागवार बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के पूर्व मैं, बजट में सम्मिलित कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में इस सम्मानित सदन को बताना चाहूँगा ।

किसानों के लिए योजनायें

- गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था करायी गयी है ।

- किसानों के ऋण की माफी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 में 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । वर्ष 2013–2014 में इस योजना के लिये 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । इस प्रकार कुल 1,650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेगें, जिससे लगभग 08 लाख किसान ऋणमुक्त होंगे ।

- हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इस प्रयोजन के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- किसान दुर्घटना बीमा हेतु 375 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- हमने ग्रामीण किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की वायदा किया था । मैं अत्यन्त हर्ष के साथ इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा 4 प्रतिशत के बजाय 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक अल्पकालिक फसली ऋण प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

- पूर्वांचल के 27 जनपदों की 2,000 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को किसानों को समय से आवश्यकतानुसार उर्वरक / बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये दिये गये हैं । इस धनराशि से समितियों द्वारा 1.46 लाख मीट्रिक टन उर्वरक तथा 46,000 कुन्तल उन्नत बीज का व्यवसाय किया गया है जिससे 7.23 लाख किसान लाभान्वित हुये हैं ।

- किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा लगभग 7.38 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक तथा 2 लाख टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण किया गया

है । इस कार्य हेतु सरकार द्वारा 100 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये योजनायें

- डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड, के0सी0 ड्रेन निर्माण एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलॉकिंग टाईल्स बिछाने हेतु 287 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- दस हजार से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों तथा दूषित पानी वाले समस्त गाँवों को भी नगरीय क्षेत्रों की तरह नल से जल उपलब्ध कराने की योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है ।
- हमारी सरकार के विशेष प्रयासों से ग्रामीण सड़कों के निर्माण व उच्चीकरण के लिये तीन हजार एक सौ सात करोड़ रुपये (3,107 करोड़ रुपये) के प्रस्ताव स्वीकृत हुये हैं ।
- स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना को अधिक परिणामपरक बनाने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन प्रदेश में लागू किया जा रहा है । ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा ।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

शहरी क्षेत्रों के विकास के लिये योजनायें

- नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 156 करोड़ रुपये, नगरीय सीवरेज योजना हेतु 120 करोड़ रुपये, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिये 130 करोड़ रूपये तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिये 110 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- "नया सवेरा नगर विकास योजना" के क्रियान्वयन के लिये, नागर स्थानीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु 900 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012–2013 की व्यवस्था से छः सौ उनसठ करोड़ रुपये (659 करोड़ रुपये) अधिक है ।
- पी0पी0पी0 मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु 195 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- नगरीय सड़क सुधार की एक नई योजना प्रस्तावित की गयी है जिसके लिए 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कमज़ोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनायें

- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 1,683 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना हेतु 1,250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु 1,200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- अल्पसंख्यक समुदाय की 10वीं पास पुत्रियों को शिक्षा अथवा विवाह हेतु "हमारी बेटी उसका कल योजना" के अन्तर्गत 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- अल्पसंख्यक समुदाय के अन्त्येष्टि स्थलों एवं कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों की चहार दीवारी निर्माण योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा के लिये अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना की जायेगी जिसमें कक्षा–6 से लेकर 12 तक शिक्षा की व्यवस्था होगी । इस हब में आवश्यकता के अनुसार आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, प्रबन्धकीय प्रशिक्षण संस्थान आदि की स्थापना की जायेगी । इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग सेवा तथा अन्य सेवाओं के लिये कोचिंग केन्द्रों की स्थापना भी इस हब में की जायेगी । इस योजना को प्रारम्भ करने के लिये 34 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को दूर किये जाने के लिए 492 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- विकलांग जन के भरण–पोषण हेतु पेंशन दिये जाने के लिये 317 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

शहरी गरीबों के लिये कल्याणकारी योजनायें

- रिक्शाचालकों को बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिये जाने की योजना के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012–2013 की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रुपये अधिक है ।
- शहरी गरीब व्यक्तियों के लिये आवास उपलब्ध कराने की योजना "आसरा" के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों तथा सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब लाभार्थी लिये जायेंगे । इस योजना के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012–2013 की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रुपये अधिक है ।
- प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सी0सी0रोड, इण्टरलॉकिंग टाईल्स, नाली, जल निकासी एंव अन्य सुविधाओं के निर्माण की योजना क्रियान्वित की जायेगी । इस हेतु 375 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- शहरी क्षेत्रों को स्लम मुक्त करने के उद्देश्य से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने की "राजीव आवास योजना" हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

महिलाओं के लिये

- भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों की 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ियाँ तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को एक–एक कम्बल दिये जाने के लिये 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- निराश्रित विधवाओं को भरण–पोषण अनुदान हेतु 608 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना हेतु 03 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अधिवक्ताओं के लिये

- अधिवक्ता कल्याण निधि को आर्थिक सहायता हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उच्च विकास दर प्राप्त करने की राह में विश्व व्यापी मन्दी

का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । विकास की सम्भावनाओं एवं आवश्यकताओं को देखते हुये सार्थक प्रयास द्वारा उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिये सरकार कटिबद्ध है । इस अवधि में 8.5 प्रतिशत की औसत विकास दर प्राप्त किया जाना लक्षित है । इसके लिये मूल ढाँचागत सुविधाओं के विकास को वरीयता प्रदान की गयी है । ऊर्जा एवं सड़कों के त्वरित विकास हेतु कदम उठाये गये हैं ।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि की विकास दर 4.9 प्रतिशत रखी गयी है । कृषि क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आय में वृद्धि के लिये कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जायेगा । किसानों को समय पर खाद एवं बीज मुहैया कराने के साथ ही सस्ते दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और अपेक्षित विनियोजन जुटाये जाने हेतु निवेश नीति, 2012 बनायी गयी है । इस नीति में क्षेत्रीय असन्तुलन को दृष्टिगत रखते हुये पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं ।

नेपाल सीमा से लगे प्रदेश के 7 जनपदों के सीमावर्ती विकास खण्डों के समग्र विकास हेतु विशेष प्रयास किये जा रहें हैं ।

नक्सल प्रभावित तीन जनपदों यथा–मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चन्दौली में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ।

मान्यवर,

अब मैं कुछ मुख्य विभागों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बजट प्रस्तावों का उल्लेख करना चाहूँगा ।

कानून व्यवस्था

प्रदेश में जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं, जिनके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित है । अपराध नियंत्रण के साथ–साथ अपराधों के पंजीकरण पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है ।

हमारी सरकार कानून का राज कायम करने के लिये प्रतिबद्ध है । पुलिस आधुनिकीकरण योजना पर बल दिया जायेगा और इसके लिए धन की कमी नहीं होने दी जायेगी ।

प्रदेश में साइबर अपराधों के अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये दो साइबर इकाइयों की स्थापना आगरा एवं लखनऊ में की गयी है ।

कृषि

वर्ष 2013–2014 में 55.81 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 11.68 लाख कुन्तल एवं रबी के अन्तर्गत 44.13 लाख कुन्तल बीज वितरित किये जाने प्रस्तावित है ।

वर्ष 2013–2014 में 108.40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें खरीफ

के अन्तर्गत 52.50 लाख मीट्रिक टन एवं रबी के अन्तर्गत 55.90 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाना प्रस्तावित है ।

वर्ष 2013–2014 में 44 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण तथा उनसठ हजार करोड़ रुपये (59,000 करोड़ रुपये) का कृषि ऋण कृषकों को उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013–2014 में 771 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट में 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पंचायती राज

बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण सेवा केन्द्रों की निर्माण योजना में गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपदों बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर में 162 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जायेगा ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 में 702 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

वर्ष 2013–2014 में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दो हजार आठ सौ तीस (2,830) हेक्टेयर में पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश में विभिन्न मसालों यथा–हल्दी, लहसुन, मिर्च, धनिया के उन्नतशील प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आच्छादित क्षेत्रफल का विस्तार कराया जा रहा है । इन कार्यक्रमों को वर्ष 2013–2014 में चार हजार सात सौ अस्सी (4,780) हेक्टेयर में चलाया जाना प्रस्तावित है ।

ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के लिये पाँच हजार सत्तासी करोड़ रुपये (5,087 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु 1.50 करोड़ रुपये की दर से कुल 756 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड से होने वाली क्षति को रोकने के लिये फायर बिग्रेड की गाड़ियाँ क्रय करने तथा निर्धन व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विधायक निधि से धनराशि स्वीकृत करने के लिये प्रावधान किये जा रहे हैं ।

दुग्ध विकास

अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के प्रदेश के सबसे बड़े डेरी प्लान्ट की स्थापना करायी जायेगी ।

पशुधन

- जनपद आजमगढ़ में एक नया पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा ।

- प्रदेश में कॉमर्शियल लेयर्स एवं ब्रॉयलर पैरेण्ट फार्म खोले जाने की नीति को क्रियान्वित किया जायेगा जिससे कुक्कुट उद्योग का प्रदेश में तेजी से विकास हो सके ।

मत्स्य

मछुआ समुदाय के सामाजिक संरक्षण हेतु 1.30 लाख समिति के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित कराया जायेगा ।

मछुआ समुदाय के आवास विहीन मछुआ परिवारों को रुपये 50,000 प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान करायी जायेगी ।

परती भूमि विकास

ऊसर सुधार परियोजना के तृतीय चरण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट में 176 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 में उपचार हेतु निर्धारित लक्ष्य 20,000 हेक्टेयर के सापेक्ष इक्कीस हजार सात सौ तिरानवे (21,793) हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन/वर्गीकरण 359 ग्रामों में किया गया है ।

बीहड़ सुधार पायलट परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 हेतु चयनित 2,000 हेक्टेयर के सापेक्ष 15 अदद जल समेट क्षेत्रों में दो हजार छः सौ चौवन (2,654) हेक्टेयर का चयन किया गया है ।

गन्ना एवं चीनी उद्योग

गन्ना किसानों के उत्पादों की विपणन सुविधाओं में विस्तार हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 63 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में गन्ना क्रय एवं चीनी विक्रय की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने के उद्देश्य से ई–टेण्डर एवं ऑन लाईन चीनी विक्रय प्रक्रिया लागू की जायेगी । घटतौली की शिकायत समाप्त करने हेतु सहकारी चीनी मिलों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल काँटा स्थापित किये जायेंगे ।

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के लिये ग्यारह हजार सात सौ बत्तीस करोड़ रुपये (11,732 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012–2013 की तुलना में 24.5 प्रतिशत अधिक है ।

सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों की कार्यकुशलता में सुधार तथा उनका वित्तीय पुनर्गठन कर आगामी तीन से पाँच वर्षों में उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा लाभ की स्थिति में लाने के लिये एक व्यापक वित्तीय पुनर्संरचना योजना अनुमोदित की गयी है जिसके लिये वर्ष 2013–2014 के बजट में 1,522 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण, क्षमता विस्तार तथा

आधुनिकीकरण कार्यों के लिए एक हजार सत्तर करोड़ रुपये (1,070 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । सार्वजनिक क्षेत्र में अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 4,433 मेगावॉट है । इसमें 1,500 मेगावॉट की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है । निजी क्षेत्र में 4,850 मेगावॉट उत्पादन क्षमता की परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, जिनसे प्रदेश को 4,580 मेगावॉट विद्युत प्राप्त होगी । संयुक्त क्षेत्र में 3,300 मेगावॉट उत्पादन क्षमता की परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, जिनसे प्रदेश को 2,191 मेगावॉट विद्युत प्राप्त होगी ।

नये विद्युत संयत्रों से विद्युत की निकासी हेतु नये ट्रांसमिशन केन्द्रों तथा ट्रांसमिशन लाईनों की स्थापना करायी जायेगी । विभिन्न क्षमताओं वाले 61 ट्रांसमिशन केन्द्रों तथा 1,837 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाईनों के अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है । वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु 33 के0वी0 क्षमता के 338 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है ।

अविद्युतीकृत एवं आंशिक रूप से विद्युतीकृत तीन हजार आठ सौ चौवन (3,854) ग्रामों तथा तीस हजार छ सौ सत्तर (30,670) मजरों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जिसकी अनुमानित लागत तीन हजार चार सौ तिरपन करोड़ रुपये (3,453 करोड़ रुपये) है ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण फीडर को अलग करने की 1,500 करोड़ रुपये की योजना पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

सड़क एवं यातायात

सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत तथा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिये लोक निर्माण विभाग के बजट में सात हजार आठ सौ अड़तालिस करोड़ रुपये (7,848 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012–2013 की बजट व्यवस्था से एक हजार दो सौ चार करोड़ रुपये (1,204 करोड़ रुपये) अधिक है। इससे उक्त कार्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है ।

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों, लघु सेतुओं के कार्यों के लिए एक हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (1,877 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पुलों के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु एक हजार एक सौ दस करोड़ रुपये (1,110 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था सम्मिलित है ।

जिला मुख्यालयों को चार लेन से जोड़े जाने हेतु 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अधिक यातायात घनत्व वाले राज्य मार्गो, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के

चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें

पूर्वांचल की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों हेतु 291 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यो के लिये 109 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

किसानों को मुफ्त एवं बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु सिंचाई विभाग के बजट में सात हजार इकसठ करोड़ रुपये (7,061 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012–2013 की बजट व्यवस्था से एक हजार आठ सौ सत्रह करोड़ रुपये (1,817 करोड़ रुपये) अधिक है ।

बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु 725 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जा रहा है जिस हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वॉटर बॉडीज के रिपेयर, रिनोवेशन एवं रिस्टोरेशन (आर0आर0आर0) सम्बन्धी परियोजना

प्रारम्भ की जा रही है जिस हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । प्रारम्भ में यह योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बाँदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झाँसी एवं ललितपुर में चलायी जायेगी । इस योजना में वॉटर बॉडीज की क्षमता की पुनर्स्थापना और मरम्मत सम्बन्धी कार्य कराये जाने से भूजल स्तर में वृद्धि होगी और कृषि की उपज भी बढ़ेगी जिससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा ।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 3,000 नलकूपों एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत 8,000 नलकूपों के कार्य प्रगति पर हैं ।

लघु सिंचाई

वर्तमान में प्रदेश का लगभग 78 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र निजी लघु सिंचाई साधनों से सिंचित है। वर्ष 2013–2014 में विभिन्न योजनाओं के लिये 340 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 8.80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा ।

निःशुल्क बोरिंग हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । डॉ0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

नगर विकास

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस

अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 975 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये तथा झील संरक्षण योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु "राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी" के कार्यों के लिये 70 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । इन कार्यों के अन्तर्गत कानपुर में सीवरेज नेटवर्क, जाजमऊ स्थित एस0टी0पी0 का अपग्रेडेशन, टैनरियों के उत्प्रवाह के शोधन एवं रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट के कार्य कराये जायेंगे ।

आवास एवं शहरी नियोजन

प्रदेश के नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है ।

लखनऊ नगर के समग्र विकास योजना की तर्ज पर लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना प्रारम्भ की जा रही है जिस हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सूचना प्रौद्योगिकी

लखनऊ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा आई0टी0सिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया है ।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन हेतु 16 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

लघु उद्योग

वर्ष 2012–2013 में माह दिसम्बर, 2012 तक अट्ठाईस हजार पाँच सौ पैंसठ (28,565) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हुई है, जिसमें दो हजार एक सौ सत्तर करोड़ रुपये (2,170 करोड़ रुपये) का पूँजी निवेश हुआ है तथा 1.79 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है । वित्तीय वर्ष 2013–2014 में भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है, ताकि अधिक से अधिक नये रोजगार के अवसर सृजित हो सकें ।

खादी एवं ग्रामोद्योग

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत में एक इकाई की स्थापना करने के उद्देश्य से वर्ष 2013–2014 में लगभग 2,500 ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य है, जिससे लगभग 60,000 लाभार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे ।

हथकरघा वस्त्रोद्योग

- मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ में हथकरघा उद्योग के लिए विपणन केन्द्र की स्थापना की जायेगी । इस हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

बुनकरों के समग्र विकास हेतु एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश

में 50 क्लस्टर संचालित हैं, जिसमें लगभग 17,000 बुनकरों को लाभ दिया जा रहा है । क्लस्टर योजना में जो हथकरघा बुनकर शामिल नहीं हैं उन्हें लाभ पहुँचाने हेतु "ग्रुप एप्रोच योजना" के द्वारा 8,000 बुनकरों को लाभ प्रदान किया जा रहा है ।

बुनकरों के स्वास्थ्य के लिये अब तक इस योजनान्तर्गत 1.78 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये हैं ।

बेसिक शिक्षा

बेसिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2013–2014 हेतु इक्कीस हजार पाँच सौ बीस करोड़ रुपये (21,520 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है । 9,770 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो रही है । इसके अतिरिक्त 72,825 प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती की कार्यवाही गतिमान है ।

वर्ष 2013–2014 में सर्व शिक्षा अभियान के लिये दो हजार दो सौ उन्नीस करोड़ रुपये (2,219 करोड़ रुपये) एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु एक हजार सात सौ उनहत्तर करोड़ रुपये (1,769 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2,311 नवीन प्राथमिक विद्यालयों तथा 313 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का कार्य गतिमान है । असेवित बस्तियाँ जो किन्हीं कारणों से छूट गयी हैं,

उनमें वर्ष 2013–2014 में नवीन विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है ।

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में दस हजार अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण के साथ–साथ बीस हजार विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2013–2014 हेतु कुल दस हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ रुपये (10,367 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

माध्यमिक विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना संचालित है । इस योजना के लिये 98 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिये 200 छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा ।

- जनपद एटा के ग्राम अमृतपुर रघुपुर तथा जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के ग्राम पंचायत सैरपुर में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना की जायेगी ।

- बख्शी का तालाब, लखनऊ के ग्राम बेहटा के जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना की जायेगी ।

- प्रदेश में एक नये सैनिक स्कूल की स्थापना की जायेगी ।
- जनपद गाजीपुर में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज परिसर में लड़कियों की शिक्षा हेतु सर सैय्यद अहमद खाँ के नाम पर एक अतिरिक्त राजकीय पुस्तकालय की स्थापना तथा प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जायेगा ।

उच्च शिक्षा

राजकीय महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार कराया जायेगा । राज्य के विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित कराये जाने की योजना क्रियान्वित की जायेगी ।

सहशिक्षा/महिला/संकाय की दृष्टि से असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा महाविद्यालय खोलने हेतु हमारी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

प्राविधिक शिक्षा

प्रत्येक मण्डल में एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है ।

- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज विहीन आगरा मण्डल के जनपद मैनपुरी में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जायेगी जिसका कार्य प्रारम्भ करने के लिये 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश में पी0पी0पी0 मॉडल पर एक इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जायेगी, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश में डिग्री स्तर के 2 तकनीकी विश्वविद्यालयो का संविलियन कर पूर्ववत् उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किये जाने तथा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर को रूड़की की भाँति विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है ।

व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पाँच सौ पन्चानवे करोड़ रुपये (595 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वित्तीय वर्ष 2013–2014 में प्रदेश में 21 नये राजकीय आई0टी0आई0 खोले जायेंगे जिस हेतु 42 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वर्तमान में संचालित राजकीय आई0टी0आई0 के सुदृढ़ीकरण हेतु 53 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा के लिये दो हजार चार सौ बीस करोड़ रुपये (2,420 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012–2013 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है ।

- मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी के रोकथाम हेतु 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जायेगी जिसका कार्य प्रारम्भ करने के लिए 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । साथ ही, एम.आर.आई. की स्थापना के लिये 08 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- आजमगढ़ में एक नया पैरा मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जायेगा । इस कार्य को प्रारम्भ किये जाने हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- मेडिकल कॉलेज कानपुर में न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना के लिए 02 करोड़ रुपये तथा मेडिकल कॉलेज मेरठ में एम0आर0आई0 व सी0टी0 स्कैन की स्थापना के लिए 08 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- राजकीय मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद में एम0आर0आई0 व सी0टी0 स्कैन की स्थापना का निर्णय लिया गया है ।

- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आई0सी0यू0 की स्थापना की जायेगी । इस हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु गरीब एवं पिछड़े वर्गो के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रुपये 25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिये आठ हजार दो सौ पच्चीस करोड़ रुपये (8,225 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 हेतु 75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश में 100 शैय्या वाले चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में उपकेन्द्रों के भवन के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

जनपद अलीगढ़ के 200 शैय्यायुक्त चिकित्सालय में क्षमता विस्तार करते हुए इसे 300 शैय्यायुक्त बनाया जायेगा ।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2013–2014 के बजट मे दो हजार सात सौ बानवे करोड़ रुपये (2,792 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

समाज कल्याण

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति मद में एक हजार चार सौ छप्पन करोड़ रुपये (1,456 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिये 25 करोड़ रुपये की की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु सहायता योजना के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 16 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु सात सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (777 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वित्तीय वर्ष 2012–2013 की बजट व्यवस्था से 100 करोड़ रुपये अधिक है ।

मान्यता प्राप्त मदरसा/मकतब में धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने की योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु एक हजार छः सौ पाँच करोड़ रुपये (1,605 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वित्तीय वर्ष 2012–2013

के बजट से एक सौ सत्रह करोड़ रुपये (117 करोड़ रुपये) अधिक है ।

पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी की योजनान्तर्गत 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012–2013 की बजट व्यवस्था से 60 करोड़ रुपये अधिक है ।

विकलांग कल्याण

विकलांग पेंशन हेतु 317 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- जनपद औरैया की हीरानगर, कन्नौज की छिबरामऊ एवं इलाहाबाद की मेजा तहसील में सामान्य बच्चों सहित दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिये कक्षा–6 से 12 तक की शिक्षा हेतु समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी । इस कार्य को प्रारम्भ किये जाने हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

महिला एवं बाल विकास

पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए दो हजार सात सौ बारह करोड़ रुपये (2,712 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अनूपुरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2013–2014 में इस योजना से लगभग 2.50 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा ।

प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु "स्टेट न्यूट्रीशन मिशन" का गठन किया जायेगा ।

सबला योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण व स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, घरेलू जीवन कौशल व व्यवसायिक कौशल संवर्धन हेतु 320 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

बालकों के उत्थान के लिये 72 जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना हो चुकी है ।

शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में इधर–उधर भटकते हुए, कूड़ा बीनने वाले तथा आश्रयहीन जरूरतमंद बालको के लिये स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 25 संवासियों की क्षमता वाले आश्रयगृह संचालित हैं ।

खेल एवं युवा कल्याण

वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिये 177 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

झाँसी में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कराया जायेगा, इटावा में एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान एवं जिम्नेजियम हाल का निर्माण कराया जायेगा, आगरा में एयरोस्पोर्ट्स प्रारम्भ कराये जायेंगे, अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी की स्थापना करायी जायेगी ।

- ओलम्पिक पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये स्वर्ण पदक विजेता को एक करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को

50 लाख रुपये तथा कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपये दिये जायेंगे ।

- खेल एवं खेल से सम्बन्धित क्रियाकलापों को बढ़ावा दिये जाने के लिए अनुदान देने की एक नई योजना प्रारम्भ की जायेगी जिसके लिये 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

राजस्व

कृषक दुर्घटना बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013–2014 में 375 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिये 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में मण्डल/जनपद /तहसीलों के अनावासीय भवन तथा आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु 144 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

न्याय

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के निर्माणाधीन नवीन भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट में 476 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रुपये 339 करोड़ की व्यवस्था तथा पुराने आवासीय एवं अनावासीय भवनों के मरम्मत हेतु 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ग्रामीण जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 113 तहसीलों पर बाह्य न्यायालय/ग्राम न्यायालय स्थापित किये जायेंगे । इस हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उच्च न्यायालय के सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में चिकित्सा हेतु रिवॉल्विंग फण्ड के लिए 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वन

सरकार ने प्रदेश में वनावरण व वृक्षावरण वृद्धि हेतु वर्षाकालीन वृक्षारोपण के साथ ही प्रत्येक जनपद में हरित पट्टी स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसके लिए 11 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पौधशाला प्रबन्ध परियोजना में 8 से 12 फुट ऊँचाई के पौधों को तैयार किये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वन्य जीवों के प्रति जन संवेदना जागृत करने के उद्देश्य से सरकार ने लखनऊ व कानपुर स्थित चिड़ियाघर का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है ।

पर्यावरण

उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्डस्ट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेन्ट तैयार किया जा रहा है । नदियों एवं प्रमुख झीलजों में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से प्रदूषणकारी स्रोतों की

पहचान हेतु रिमोट सेन्सिंग आधारित अध्ययन कराये जा रहे हैं ।

उद्यमियों के उपयोगार्थ टैनरी इन्डस्ट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेन्ट तथा फ्लाई ऐश यूटीलाइजेशन संबंधी डॉक्यूमेन्ट आई0आई0टी0, कानपुर के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है ।

पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये सभी छोटे कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (ई0टी0पी0) की स्थापना अनिवार्य की गयी है ।

पर्यटन

आगरा में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगरा के ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों के पुनर्निर्माण और उच्चीकरण का कार्य कराया जायेगा जिसके लिये 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मथुरा–वृंदावन–गोवर्धन क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए उसका व्यापक सौन्दर्यीकरण कर इन क्षेत्रों की तीर्थ यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाया जा रहा है । मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जायेगा ।

अयोध्या में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जायेगा । चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा ।

- प्रदेश में पर्यटन एवं शिल्प कलाओं के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कराये

जाने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- दुधवा नेशनल पार्क में स्थित गेस्ट हाउस का उच्चीकरण तथा पार्क की सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा जिसके लिये 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । कतरनिया घाट में भी पर्यटन विकास का कार्य कराया जायेगा ।

कुशीनगर बुद्ध परिनिर्वाण स्थल में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

संस्कृति

प्रदेश में संगीत, साहित्य, क्रीड़ा, ललित कलाएं तथा अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले ख्याति प्राप्त महानुभावों और उत्कृष्ट कलाकारों, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया हो, को 11 लाख रुपये नकद धनराशि, अंगवस्त्र एवं ताम्रपत्र/स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप "यश भारती सम्मान" के रूप में दिया जायेगा ।

- राजापुर, चित्रकूट में तुलसी स्मारक प्रांगण में लोहिया प्रेक्षागृह की स्थापना की जायेगी ।

- आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निमार्ण कराया जायेगा ।

- विख्यात समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की स्मृति में जनेश्वर मिश्र पुस्तकालय की स्थापना इलाहाबाद में की जायेगी ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्रगति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्रीकर, मनोरंजन कर, भू–राजस्व आदि की वसूली होती है ।

वाणिज्य कर

वर्ष 2013–2014 में वाणिज्य कर से तैंतालीस हजार नौ सौ छत्तीस करोड़ रुपये (43,936 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान है जो वर्ष 2012–2013 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है ।

स्टाम्प शुल्क

वर्ष 2013–2014 में स्टाम्प शुल्क से दस हजार पाँच सौ पचपन करोड़ रुपये (10,555 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान है जो वर्ष 2012–2013 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है ।

आबकारी

वर्ष 2013–2014 में आबकारी शुल्क से बारह हजार चौरासी करोड़ रुपये (12,084 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है जो वर्ष 2012–2013 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है ।

मोटर वाहन एवं यात्रीकर

वर्ष 2013–2014 में मोटर वाहन एवं यात्रीकर से तीन हजार सात सौ तेरह करोड़ रुपये (3713 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है जो वर्ष 2012–2013 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2013–2014 में दो लाख पन्द्रह हजार नौ सौ उन्नीस करोड़ बयासी लाख रुपये (2,15,919.82 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।
- कुल प्राप्तियों में एक लाख सतहत्तर हजार सात सौ अड़तालीस करोड़ इक्कीस लाख रुपये (1,77,748.21 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा अड़तीस हजार एक सौ इकहत्तर करोड़ इकसठ लाख रुपये (38,171.61 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।

- वर्ष 2013–2014 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख चालीस हजार छः सौ इक्यावन करोड़ रुपये (1,40,651 करोड़ रुपये) है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश अड़सठ हजार चार सौ अट्ठावन करोड़ रुपये (68,458 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2013–2014 में कुल व्यय दो लाख इक्कीस हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रुपये (2,21,201.19 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।
- कुल व्यय में एक लाख सड़सठ हजार आठ सौ बानवे करोड़ बीस लाख रुपये (1,67,892.20 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा तिरपन हजार तीन सौ आठ करोड़ निन्यानवे लाख रुपये (53,308.99 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।
- वर्ष 2013–2014 के बजट में सड़सठ हजार सोलह करोड़ तिरपन लाख रुपये (67,016.53 करोड़ रुपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है ।

राजस्व बचत

- वर्ष 2013–2014 में नौ हजार आठ सौ छप्पन करोड़ एक लाख रुपये (9,856.01 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है ।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2013–2014 में तेईस हजार नौ सौ तेरह करोड़ उन्तीस लाख रुपये (23,913.29 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2013–2014 में घाटा पाँच हजार दो सौ इक्यासी करोड़ सैंतीस लाख रुपये (5,281.37 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।

लोक लेखे से समायोजन

वर्ष 2013–2014 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये तीन हजार पाँच सौ पचास करोड़ रुपये (3,550 करोड़ रुपये) लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2013–2014 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम एक हजार सात सौ इकत्तीस करोड़ सैंतीस लाख रुपये (1,731.37 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2013–2014 में प्रारम्भिक शेष दो हजार नौ सौ सत्तावन करोड़ नब्बे लाख रुपये (2,957.90 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष

एक हजार दो सौ छब्बीस करोड़ तिरपन लाख रुपये (1,226.53 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है ।

मान्यवर, मैं मंत्रि–परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री आनन्द मिश्र और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

इस बजट के माध्यम से हमारा प्रयास है कि प्रदेश के किसान, युवा वर्ग, बेरोजगार, बालिकायें एवं महिलायें, अल्पसंख्यक, विपन्न, असहाय, कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोग भी जीवन और भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकें और एक नई ऊर्जा के साथ स्वयं तथा समाज की उन्नति के लिये कृतसंकल्प

होकर विकास के एक नये युग का सृजन कर सकें । मैं प्रदेश के हर वर्ग/समुदाय का आह्वान करता हूँ कि आइये हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करें ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2013–2014 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

माघ 30, शक संवत् 1934,
तदनुसार,
दिनाँक : 19 फरवरी, 2013